

स्वर्णिम प्रदेश

* वर्ष: 07 * अंक : 270 * मुंबई, शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 * पेज: 6 * मूल्य: 2 रुपये * संपादक: सुनील कुमार तिवारी

थाईलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह मोदी-मोदी के नारों से गूंजा बैंकॉक

विशेष संवाददाता
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर 'मोदी-मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारों के बीच लोगों ने तिरंगे लहराए। कई महिलाएं पीएम मोदी से मिलकर भावुक हो गईं, एक महिला ने तो उनका हाथ चूमकर रोते हुए अपनी भावनाएं प्रकट की।
भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत
थाईलैंड में बसे भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी के स्वागत में देशभक्ति के नारे लगाए। मोदी ने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा: 'बैंकॉक में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आभारी हूँ। भारत और थाईलैंड के बीच एक गहरा सांस्कृतिक बंधन है, जो हमारे लोगों के माध्यम से मजबूत होता रहता है।'



थाईलैंड की पीएम पाइत्तान्तरन शिनवात्रा से व्यापारिक वार्ता

थाईलैंड पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री पाइत्तान्तरन शिनवात्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-थाईलैंड के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही पर्यटन, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। (शेष पेज ०२ पर)

मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी महामंडल की आय बढ़ाने के लिए नई विज्ञापन नीति तैयार करने के लिए निर्देश

संवाददाता
मुंबई। एसटी महामंडल की बसों और बस स्टैंड पर विज्ञापनों से होने वाली आय को १०० करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए व्यापक नई नीति तैयार करने के निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिए हैं। परिवहन आयुक्तालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री सरनाईक ने कहा कि वर्तमान में जिन विज्ञापन एजेंसियों को कार्य दिया गया है, उनसे अपेक्षित आय नहीं मिल रही है। इसलिए, उनके अनुबंध रद्द कर अधिक आय देने वाली एजेंसियों का चयन किया जाएगा। वर्तमान में विज्ञापन से एसटी को २२-२४ करोड़ रुपये की आय होती है, जिसे १०० करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
बसों और बस स्टैंड के सुधार पर जोर
नई बसों की खरीद में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के लिए उपयुक्त पैलन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी बसों में भी यह लागू किया जाएगा। साथ ही, महत्वपूर्ण बस स्टैंडों के सुधार के लिए भी योजना बनाई जाएगी। महिलाओं की सुविधा के लिए एसटी को डीजल आपूर्ति करने वाली कंपनियों को उनके सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से बस स्टैंडों पर स्वच्छ शौचालय और महिला प्रतीक्षालय बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री सरनाईक ने यह भी कहा कि भविष्य में डीजल की निविदाएं जारी करते समय सीएसआर फंड की शर्त जोड़ी जानी चाहिए।



इलेक्ट्रिक बस अनुबंध पर सख्त रुख

एसटी महामंडल को किराए पर दी जाने वाली ५,१५० इलेक्ट्रिक बसों में से केवल २२० बसें ही आपूर्ति की गई हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री सरनाईक ने संबंधित कंपनियों को अंतिम नोटिस देने का निर्देश दिया। यदि इसके बाद भी बसों की आपूर्ति नहीं होती, तो उनके अनुबंध रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
नई बसें हर डिपो तक पहुंचेगी
इस साल एसटी महामंडल के बेड़े में २,६४० नई लालपरी बसें शामिल की जा रही हैं। इनमें से मार्च के अंत तक ८०० बसें १०० डिपो में भेजी जा चुकी हैं। मंत्री सरनाईक ने निर्देश दिया कि अगले दो महीनों में सभी २५१ डिपो तक नई बसें पहुंचाई जाएं। नई बसों को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसलिए, भविष्य में भी उच्च गुणवत्ता वाली बसें शामिल करने और सभी बसों में जीपीएस व सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए।

वक्फ बिल: मोदी सरकार पर गरजे संजय राउत बोले- मुसलमानों की इतनी चिंता तो जिन्ना ने नहीं की

संवाददाता
मुंबई। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में इस पर चर्चा जारी है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक विषयों को चर्चा में ला रही है।
'असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश':
सांसद संजय राउत
संजय राउत ने कहा, 'कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर २६ प्रतिशत टैरिफ का आक्रमण किया। उसी दिन सरकार वक्फ बिल लेकर आई, ताकि असली मुद्दों को दबाया जा सके। जब भी महंगाई और रोजगार पर बात आती है, तो सरकार धार्मिक मुद्दे उठाकर २-५ दिन की चर्चा कराती है।' राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधते हुए कहा, 'कल से आप लोग मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, उतनी तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की होगी। आपके भाषणों को सुनकर ऐसा लगता है कि जिन्ना की आत्मा आपकी सरकार में प्रवेश कर गई है। पहले हमें लगा था कि हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपके भाषणों से लगता है कि आप हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं।'



'आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी?'

संजय राउत ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, 'आप मुसलमानों को चोर, जमीन छीनने वाला, मंगल सूत्र लूटने वाला, देशद्रोही कहते थे। अब आप ही उनकी संपत्ति के रखवाले बन गए? आप हिंदुओं की जमीन नहीं बचा पाए और अब मुस्लिमों की जमीन बचाने की बात कर रहे हैं?'
अमेरिका के टैरिफ हमले पर भी साथ निशाना
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने अमेरिका द्वारा भारत पर २६ प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति जब भारत के प्रधानमंत्री को 'महान व्यक्ति' कहते हैं, तो सरकार इसका ढोल पीटने लगती है। लेकिन देखिए, अब अमेरिका ने हमें क्या बना दिया? विदेश मंत्री विशेषज्ञ होने के बावजूद, अमेरिका बार-बार भारत का उपहास उड़ा रहा है। यूरोपीय संघ इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है, (शेष पेज ०२ पर)'

वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू को पड़ा भारी! 2 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा

संवाददाता
पटना। वक्फ संशोधन विधेयक पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के रुख से नाराज होकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। देर रात लोकसभा में यह विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने व्यापक विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया।
नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने जताई नाराजगी
अंसारी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को लिखे अपने पत्र में पार्टी के इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने जेडीयू पर धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए भरोसा किया था, लेकिन अब यह भरोसा टूट चुका है। उन्होंने लोकसभा में जेडीयू नेता ललन सिंह द्वारा दिए गए भाषण की आलोचना करते हुए इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। अंसारी ने इसे पसमांदा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण करार दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा- हम जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को जेडीयू की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर अटूट विश्वास था। हालांकि, अब यह विश्वास टूट गया है। वक्फ बिल पर जेडीयू द्वारा लिए गए रुख ने हमें गहरा सदमा दिया है। लोकसभा में जिस तरह ललन सिंह ने बिल का समर्थन किया, वह बेहद निराशाजनक है। (शेष पेज ०२ पर)



'बांद्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' के तहत घरों का सपना होगा पूरा: पालकमंत्री एड.आशिष शेलार

संवाददाता
मुंबई। विकास कार्यों के दौरान मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक होता है। 'बांद्रा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' के तहत बांद्रा पूर्व के गौतम नगर क्षेत्र में कई परिवारों का सपना पूरा हो रहा है, ऐसा मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एड. आशिष शेलार ने कहा। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के तहत पुनर्वसित किए जा रहे निवासियों को उनके नए घरों के करार पत्र वितरित करने का कार्यक्रम मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। पालकमंत्री शेलार ने इस अवसर पर १० लाभार्थियों को उनके घर के करार पत्र सौंपे। इस दौरान मुंबई उपनगर जिले के जिलाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। पालकमंत्री शेलार ने बताया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गणेश उत्सव से (शेष पेज ०२ पर)



स्वर्गट बलात्कार मामला: अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाने से किया इनकार

संवाददाता
पुणे। पुणे की एक अदालत ने बुधवार को स्वर्गट बलात्कार मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाडे की पुलिस हिरासत बढ़ाने की अपराध शाखा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि पुलिस ने हिरासत बढ़ाने के लिए पर्याप्त ठोस कारण नहीं दिए। गाडे को २८ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और शुरू में उसे १२ मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। हालांकि, अपराध शाखा ने आगे की हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया कि जांच के हिस्से के रूप में आरोपी की हरकतों और व्यवहार के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए उन्नत ३डी तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। लेकिन अदालत ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी हो गई। २६ वर्षीय महिला ने स्वर्गट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान के बाद २८ फरवरी को तड़के करीब १:१५ बजे गाडे को एक गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि उसके खिलाफ डकैती के छह फ्तारने मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई और डीएनए सैंपल एकत्र किया। हिरासत के दौरान, उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया और उस (शेष पेज ०२ पर)



मुंबई। चिली गणराज्य के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ताज होटल में शिष्टाचार मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने को लेकर सकारात्मक चर्चा की। इस मौके पर राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, भारत की चिली में उच्चायुक्त अभिलाषा जोशी, चिली गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हेसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विपणन) डॉ. राजगोपाल देवरा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बीएमसी या भ्रष्टाचार मार्केटिंग कंपनी? डी वार्ड के भ्रष्ट डीईओ दिलीप अहिरे पर मेहरबान अश्विनी जोशी



वी बी माणिक
मुंबई। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अब एक भ्रष्टाचार मार्केटिंग कंपनी बन गई है, जहां बिना लूट-खसोट और बेईमानी के कोई काम नहीं होता। यहां सिपाही से लेकर आयुक्त तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन ईमानदारी का चोला पहनकर बैठते हैं। गरीबों को लूटने वाले ये अधिकारी अवैध काम करने वालों के इशारों पर नाचते हैं। बीएमसी में अवैध निर्माण का खेल बिना नियम-कानून की परवाह किए खुलेआम चलता है। डी विभाग का कार्यकारी अभियंता और पदनिर्देशित अधिकारी (DO) दिलीप संतोष अहिरे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। १९ अप्रैल २०२१ से सहायक अभियंता के रूप में तैनात अहिरे ने १ जुलाई २०२२ को डी वार्ड में ही टेंडर भरकर कार्यकारी अभियंता का पद हासिल कर लिया। सवाल यह है कि किस नियम के तहत उसकी पोस्टिंग उसी वार्ड में हुई? क्या अति-आयुक्त अश्विनी जोशी इस पर कोई कार्यवाही करेंगी या फिर उन्हें भी भ्रष्टाचार का आशीर्वाद प्राप्त है?
अहिरे और उसकी पूरी टीम अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगी हुई है। बीएमसी में नगर अभियंता का कार्यालय अब दलालों और बिल्डर माफियाओं की शरणस्थली बन चुका है। अधिकारी बंद कमरों में बैठकर वसुली करते हैं, लेकिन आम नागरिकों से मिलने से कतराते हैं। नगर अभियंता और डायरेक्टर मिलकर पोस्टिंग और ट्रांसफर का खेल खेलते हैं, जिसमें सिर्फ पैसा चलता है। आज बीएमसी पूरी तरह भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। अति-आयुक्त अश्विनी जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस लूट में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि मुंबई के प्रत्येक वार्ड में जेई, एसई और एई की नियुक्ति बिना टेंडर के नहीं होती। बीएमसी अब शहर की सेवा करने के बजाय नागरिकों का खून चूसने वाली संस्था बन गई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को शर्म आनी चाहिए, जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। मुंबई के नागरिकों को इस लूट के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना बीएमसी का यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा।

खंडवा में कुएं की सफाई करने उतरे 8 लोग जहरीली गैस की चपेट में, 4 की मौत

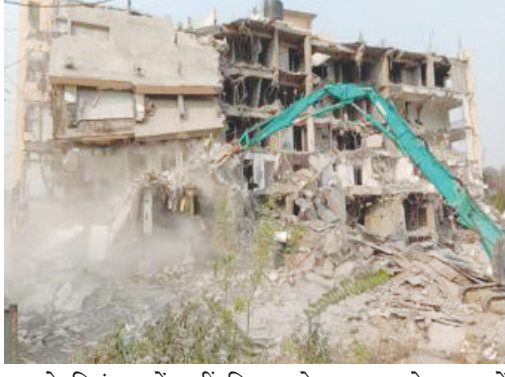


संवाददाता
खंडवा। गणगौर माता विसर्जन के लिए कुएं की सफाई के दौरान गुरुवार को जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ८ लोग कुएं में डूब गए। शाम ७ बजे तक ४ लोगों के शव निकाले जा चुके थे, जबकि शेष ४ की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआईआरएफ की टीमों रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। यह हादसा खंडवा के छैगांवमाखन क्षेत्र के ग्राम कोंडावत में हुआ, जहां गणगौर विसर्जन से पहले सफाई के लिए दो लोग कुएं में उतरे और जहरीली गैस के कारण उनका दम घुट गया। उन्हें बचाने के लिए ६ और लोग कुएं में उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। छैगांवमाखन और पंधाना थाने की पुलिस टीम एसडीआईआरएफ के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। जहरीली गैस के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते एसडीआईआरएफ कर्मी ऑक्सीजन मास्क पहनकर कुएं में उतरे और ४ शव बाहर निकाले। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कुनबी पटेल समाज की माता का विसर्जन होना था और परंपरा के अनुसार लोग कुएं की सफाई कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय मौके पर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस तैनात की गई है ताकि रेस्क्यू किए गए लोगों के इलाज में कोई बाधा न आए। इस हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि प्रशासन लगातार बचाव अभियान चला रहा है।

खारघर में सिडको की 100वीं तोड़क कार्रवाई

संवाददाता

नवी मुंबई। खारघर में सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी 100वीं कार्रवाई करते हुए एक अनधिकृत इमारत को ध्वस्त कर दिया। यह इमारत पहले 2014-15 में सिडको की कार्रवाई का सामना कर चुकी थी, जिसके बाद छह साल तक यह जमीन खाली पड़ी रही। हालांकि, जब सिडको भूखंड पर कब्जा करने में विफल रहा, तो दो साल पहले एक नए बिल्डर ने साइट पर पुनर्निर्माण किया और कई फ्लैट बेच दिए। मूल और नए बिल्डर के बीच विवाद बढ़ने के बाद मामला राज्य मंत्रालय तक पहुंचा, जिसके बाद सिडको को हस्तक्षेप करना पड़ा। सिडको के मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मंगडिया, 40 से अधिक पुलिसकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सैकड़ों श्रमिकों की मौजूदगी में इस इमारत को गिराया गया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर सिडको की अतिक्रमण नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों ने पूछा कि अगर सिडको ने अवैध निर्माण हटाने के बाद जमीन को



अपने नियंत्रण में नहीं लिया, तो अपराध दोबारा क्यों हुआ? सिडकोअधिकारियों ने नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के झंसे में न आने की अपील की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंगडिया ने कहा, 'अवैध निर्माणों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। खारघर में यह 100वीं तोड़फोड़ थी। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।'

क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 9930 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि अज्ञात जालसाज ने कंपनी की बैंकिंग से जुड़ी ईमेल आईडी हैक कर ली थी। इसके बाद, हैकर ने कंपनी के नाम से कोटक महिंद्रा बैंक को झूठे ऑपरेशनल अनुरोध भेजे, जिससे बैंक को गुमराह किया गया। इस धोखाधड़ी के जरिए जालसाजों ने कंपनी के खाते से दो अलग-अलग खातों में 99.34 करोड़ रूपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही व्यवसायी को शक हुआ, उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलते ही एनसीसीआरपी पोर्टल पर मामला दर्ज किया और बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय किया। उनकी तेजी से की गई कार्रवाई के कारण 99.99 करोड़ रूपए की राशि को फ्रीज कर लिया गया। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह घटना 3 अप्रैल को दोपहर करीब 9:30 बजे हुई। जैसे ही व्यवसायी ने अपने बैंक खाते से 99.99 करोड़ रूपए के अनधिकृत लेनदेन को देखा, उसने तुरंत साइबर

पवई के व्यवसायी की ईमेल आईडी हैक, साइबर पुलिस ने 11.19 करोड़ रूपए बचाए

संवाददाता

मुंबई। मुंबई में साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पवई के एक व्यवसायी की ईमेल आईडी हैक कर ली गई। हालांकि, समय पर की गई शिकायत और साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण 99.99 करोड़ रूपए की राशि को फ्रीज कर लिया गया। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह घटना 3 अप्रैल को दोपहर करीब 9:30 बजे हुई। जैसे ही व्यवसायी ने अपने बैंक खाते से 99.99 करोड़ रूपए के अनधिकृत लेनदेन को देखा, उसने तुरंत साइबर

महाराष्ट्र की जेलों में भगवद गीता की शिक्षा से कैदियों में आ रहा सकारात्मक बदलाव

संवाददाता

मुंबई। क्रोध, द्वेष और नफरत के कारण या परिस्थितियोंवश अपराध हो जाते हैं, लेकिन यदि ऐसे अपराधियों के जीवन में भगवद गीता के माध्यम से सकारात्मकता लाई जाए, तो उनके जीवन में एक नई सुबह आ सकती है। महाराष्ट्र की जेलों में यही बदलाव देखा जा रहा है, जहाँ 990 कैदी भगवद गीता के माध्यम से साधना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल के तहत, अब जेलों में भगवद गीता के श्लोक गूँज रहे हैं। पिछले एक साल से गीता परिवार संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र की केंद्रीय जेलों में ऑनलाइन भगवद गीता कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित गीता परिवार के स्वयंसेवक इस पहल में प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक गीता परिवार द्वारा 92 लाख से अधिक साधकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह कक्षाएँ पूरी तरह नि:शुल्क हैं और 93 भाषाओं में संचालित की जाती हैं। हर सत्र 40 मिनट का होता है, जिसमें गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है। पहली कक्षा दिसंबर 2023 में छत्रपति संभाजीनगर जेल में शुरू हुई थी। इसके बाद इसे कोल्हापुर, नासिक, ठाणे, तलोजा और येरवडा जेलों तक विस्तारित किया गया। इस समय छत्रपति संभाजीनगर जेल से 24, ठाणे से 34, कोल्हापुर से 44, नासिक से 40, तलोजा से 34 और येरवडा से 90 कैदी इस कार्यक्रम से जुड़े चुके हैं। कुल मिलाकर, 990 कैदी गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। गीता परिवार की कक्षाएँ



चार चरणों में संचालित होती हैं, जिनमें पहले स्तर में 2 अध्याय, दूसरे में 4 अध्याय, और तीसरे व चौथे स्तर में 6-6 अध्याय सिखाए जाते हैं। वर्तमान में, ठाणे, नासिक, कोल्हापुर और तलोजा जेलों में तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा होने वाला है, जिसमें 92 अध्यायों का अध्ययन हो चुका है। गीता परिवार की ओर से पठनीय गीता पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। जेल प्रशासन और कैदी दोनों ही इस पहल से संतुष्ट हैं। येरवडा महिला जेल में भी सीधे कक्षाएँ आयोजित की गईं, जबकि पुणे कैदियों के लिए प्रत्येक रविवार को प्रेरणादायक व्याख्यान दिए जाते हैं। शनिवार और रविवार को कैदियों द्वारा सीखे गए श्लोकों की व्याख्या की जाती है और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। इस पहल से कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। जेल प्रशासन को विश्वास है कि इस तरह के प्रयासों से कैदी अपने परिवारों में वापस जाकर एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। भगवद गीता की यह शिक्षा उन्हें आध्यात्मिक संतुलन प्रदान कर रही है और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल रही है।

अश्विनी बिदरे हत्याकांड में 5 अप्रैल को आ सकता है फैसला

संवाददाता

नवी मुंबई। नवी मुंबई के बहुचर्चित अश्विनी बिदरे हत्या मामले में शनिवार, 4 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। मामला पनवेल सत्र न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी पालदेवर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिससे करीब सात साल से चल रही सुनवाई का अंत हो सकता है। मुख्य आरोपी बर्खास्त पुलिस निरीक्षक अभय कुर्दकर और अन्य सह-आरोपियों के भाग्य का फैसला अगले दो दिनों में हो सकता है। अदालत ने 24 गवाहों की जांच की है और लंबे समय से अनुमान था कि अप्रैल की शुरुआत में फैसला आ सकता है।



गया। शव के टुकड़ों को 24 किलो के धातु के ब्लॉक्स से बांधकर वसई खाड़ी में डुबो दिया गया। जिस दुकान से ये वजन खरीदे गए थे, उसकी भी पहचान कर ली गई है।
हत्या के बाद भी चालाकी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या के बाद कुर्दकर ने अश्विनी के फोन का इस्तेमाल कर उसके परिवार और विभाग को संदेश भेजे कि वह उत्तर भारत में ध्यान शिविर के लिए जा रही है। इसके अलावा, कुर्दकर ने अपने गश्त ज्यूटी का गलत रिकॉर्ड तैयार किया और वाहन की रीडिंग में छेड़छाड़ कर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश की। पाटिल और कुर्दकर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड (CDR) से यह स्पष्ट हुआ कि 99 अप्रैल 2019 को दोनों की लोकेशन एक ही स्थान पर थी। इसी दिन अश्विनी बिदरे को आखिरी बार देखा गया था। तीनों की लोकेशन 99 अप्रैल को वसई क्रीक के पास थी और उसके बाद बिदरे लापता हो गईं। 98 अप्रैल को अश्विनी का फोन आखिरी बार ऑन हुआ और फिर कभी चालू नहीं हुआ।

महाराष्ट्र में ग्लोबल स्किल सेंटर की स्थापना को लेकर सिंगापुर से सहयोग: मंत्री मंगलप्रभात लोढा

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण देकर वैश्विक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसी दिशा में, सिंगापुर के मॉडल पर महाराष्ट्र में एक ग्लोबल स्किल सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसी संदर्भ में आज कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने सिंगापुर के वाणिज्य दूत ऑंग मिंग फुंग से मंत्रालय में मुलाकात कर इस परियोजना पर चर्चा की। मंत्री लोढा ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी होते ही महाराष्ट्र के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेड्स में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।



सिंगापुर के वाणिज्य दूत ने जताई सहमति

बैठक के दौरान सिंगापुर के वाणिज्य दूत ऑंग मिंग फुंग ने महाराष्ट्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्रों पर संतोष व्यक्त किया और राज्य के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण देने पर सहमति जताई। इस बैठक में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की संचालिका श्रीमती माधवी सरदेशमुख, कौशल विकास सोसायटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित थे। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज (ITEES) में वैश्विक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इस पहल के माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोजेक्ट्स में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, वे आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स, एआई टेक्नोलॉजी, औद्योगिक प्रणाली और सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सिंगापुर के ग्लोबल स्किल सेंटर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे छात्रों को वैश्विक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। इसी दिशा में, महाराष्ट्र सरकार कौशल विकास विभाग के जरिए युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर सृजित करने का प्रयास कर रही है। मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने कहा कि सिंगापुर के वाणिज्य दूत ऑंग मिंग फुंग के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द ही इस विषय पर एक समझौता (MoU) किया जाएगा।

बीएमसी के-ईस्ट वार्ड का कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

संवाददाता

मुंबई। मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में बीएमसी के के-ईस्ट वार्ड के एक कर्मचारी संदीप जोगदंडकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीएमसी में सहायक के रूप में कार्यरत था। एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ठेले बेचने और किराए पर देने का व्यवसाय करता है। 91 जनवरी 2024 को, बीएमसी के/ईस्ट वार्ड के रखरखाव विभाग द्वारा उसके ठेले बनाने के उपकरण जब्त कर लिए गए। शिकायतकर्ता ने अगले दिन अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 29 जनवरी 2024 को उसने एक अधिकारी से संपर्क किया, जिसने बताया कि उसका सामान फेंक दिया गया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। बाद में, 29 मार्च 2024 को, शिकायतकर्ता को अपने परिचितों से पता चला कि उसका सामान संदीप जोगदंडकर द्वारा बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने एक परिचित को जोगदंडकर से मिलने भेजा, जिसके बाद जोगदंडकर ने शिकायतकर्ता से खुद फोन पर संपर्क किया और जेबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास मिलने को कहा। वहां उसने शिकायतकर्ता से सामान वापस देने के लिए 94,000 रुपये की रिश्वत मांगी, जिसे बातचीत के बाद 92,000 रुपये तक कम कर दिया गया। शिकायतकर्ता सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने 2 अप्रैल 2024 को एसीबी मुंबई कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जाल बिछाया और संदीप जोगदंडकर को 92,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।



मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाने में बेवारिस मोबाइल फोन की नीलामी

संवाददाता

मुंबई। मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाने में विभिन्न अपराधिक मामलों में जब्त किए गए और जिनके दावेदार, मालिक या वारिस सामने नहीं आए हैं, ऐसे मोबाइल फोन की नीलामी आयोजित की जा रही है। यह नीलामी 4 अप्रैल 2024 को सुबह 99:30 बजे से दोपहर 92:30 बजे तक होगी। मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एच. टी. कुंभार ने आम नागरिकों से इस नीलामी में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नीलामी में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक पात्रता पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। रेलवे पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर इनके मालिक या वारिस अपने अधिकार का दावा नहीं करते, तो ऐसे सामानों की सरकारी नियमों के तहत नीलामी की जाती है। इस प्रक्रिया से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और जब्त किए गए सामान का उचित उपयोग संभव हो पाता है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक नागरिकों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित रहने की सलाह दी गई है।



भागशाला मैदान डोंबिवली में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ



संवाददाता

ठाणे। ठाणे जिले के नजदीक डोंबिवली (पश्चिम) के भागशाला मैदान (स्टेशन से 4 मिनट की दूरी पर) में शुक्रवार, 4 अप्रैल 2024 से सोमवार, 9 अप्रैल 2024 तक 908 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ भूमि पूजन से किया गया। यह आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में, डोंबिवली गायत्री परिवार की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती संध्याताई डोंबिवलीकर, अनंत प्रसाद त्रिपाठी, आशीष कुमार सिंह, जयवंत झुंझाराव के संयोजन तथा शांतिकुंज हरिद्वार के आचार्यों की उपस्थिति में संपन्न होगा। गायत्री धाम प्रतापगढ़ के आचार्य राजेश पांडे एवं राष्ट्रीय कवि अनिल कुमार राही ने कवि एवं पत्रकार विनय शर्मा दीप को बताया कि महायज्ञ का शुभारंभ 8 अप्रैल को कलश शोभायात्रा, शांतिकुंज गायत्री द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रदर्शनी, गरबा, आरती एवं प्रसाद के साथ होगा। 4 अप्रैल को देव पूजन, गायत्री महायज्ञ, संस्कार (जनेऊ) एवं संगीत प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। 6 अप्रैल को देव पूजन के साथ 99,999 दीप प्रज्वलन एवं अतिथि सम्मान समारोह होगा, जबकि 9 अप्रैल को देव पूजन, गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। आयोजकों ने मुंबई, नवी मुंबई एवं ठाणे महानगर के नागरिकों तथा गायत्री परिवार से जुड़े सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों से इस महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है।

महाराष्ट्र एफडीए का विशेष दूध जांच अभियान: 1.5 लाख लीटर दूध की जांच, 108 सैंपल लिए गए



संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) राज्य के नागरिकों को स्वस्थ, शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू कर रहा है। हाल ही में दूध में मिलावट के बढ़ते मामलों को देखते हुए, एफडीए ने 9 अप्रैल 2024 की रात से 2 अप्रैल 2024 की सुबह तक मुंबई में प्रवेश करने वाले दूध टैंकरों की विशेष जांच अभियान चलाया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरोहरी जिरवाल के नेतृत्व में तीन मुख्य जांच चौकियों- मानखुर्द (वाशी), दहिसर और ऐरोली पर दूध टैंकरों की कड़ी निगरानी की गई। इस दौरान कुल 99 दूध टैंकरों में 9,49,298 लीटर दूध की जांच की गई, जिसमें मानखुर्द चेक पोस्ट पर 49 वाहनों में 9,04,432 लीटर, दहिसर चेक पोस्ट पर 90 वाहनों में 29,908 लीटर और ऐरोली चेक पोस्ट पर 91 वाहनों में 99,642 लीटर दूध की जांच की गई। इसके अलावा, विभिन्न ब्रांडों के 908 दूध के नमूने (पैक और खुले दूध) लिए गए, जिनकी प्रयोगशाला जांच की जा रही है, और रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एफडीए विशेष अभियान चला रहा है, जिसे मंत्री नरोहरी जिरवाल, राज्य मंत्री योगेश कदम और एफडीए आयुक्त राजेश नारवेकर के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। भले ही ग्रेटर मुंबई डिवीजन में स्टाफ की कमी बनी हुई है, फिर भी एफडीए अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ दूध की गुणवत्ता पर नजर बनाए हुए हैं। यह अभियान महाराष्ट्र सरकार की खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के लोगों को शुद्ध और मिलावट रहित दूध मिले।

Lok Sabha confirms imposition of President's rule in Manipur

New Delhi: The Lok Sabha early Thursday adopted a Statutory Resolution confirming the imposition of President's rule in Manipur with opposition supporting the decision but slamming the Centre for the situation in the state.

Replying to a short debate, Union Home Minister Amit Shah said the government has taken all possible steps to bring back normalcy in the restive northeastern state. He said there has been no violence in Manipur in the last four months, adding that talks were on with both Meitei and Kuki communities for a peaceful solution. "By and large the situation is peaceful. As long as people are in camps, I would not say the situation is satisfactory. The government is taking all possible steps to restore peace in Manipur," he said. The home minister said the ethnic violence in Manipur had started following an order of the state's high



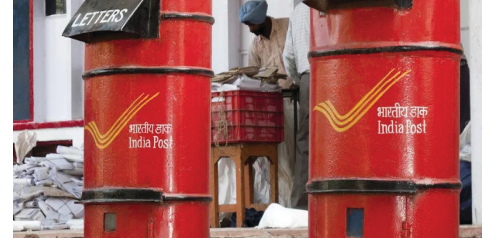
court. "The day the order came, we sent the central forces by air. There was no delay on our part (in taking action)," he said. He said, so far, 260 people have died in the violence that started in May 2023 and 80 per cent of them lost their lives within the first month.

Shah said he did not want to compare the violence that had taken place during the tenure of the previous governments but wanted to tell the House about the clashes between the Naga and Kuki communities that took place in the 1990s over five years. "Sporadic

violence continued for a decade where 750 people lost their lives. There were Kuki-Paite clashes in 1997-98 when 352 people were killed. In the Meitei-Pangal clashes in the 1990s, over 100 people died. Neither the then prime minister nor the then home minister visited Manipur," he said. The home minister said an impression has been given that violence erupted only during the BJP rule, which is not correct. Earlier, participating in the debate, Congress leader Shashi Tharoor said his party supported the resolution but wanted the restoration of peace and stability in the state. "End insurgency, restore peace and stability, promote dialogue with each other, promote inclusivity," he said. Sayani Ghosh of the Trinamool Congress said her party too supports the resolution but favours early restoration of peace. DMK's K Kanimozhi said "divisive" politics should come to an end in Manipur.

Road ahead for Post Office in India

New Delhi: Till very recently, post offices in India were functioning as per provisions of a British era Indian Post Office Act of 1898. Even though post office performs many functions other than mail delivery, the Act identified post office mainly as an instrument of mail delivery and money order payment. Present Government not only reposed its trust in the post office as an arm of the Government of India, but has also empowered it in many ways since 2014. Some of the major initiatives are detailed below. First and foremost, the Act itself has been repealed and a new Post Office Act 2023 has been passed by the Parliament in December, 2023. The Act embodies the concept of Ease of Living and Ease of doing Business in the 16 sections. Through this enactment, post office has been converted from a mail delivery arm of the Government to service



delivery. With technological tools, it's possible today to deliver many services by the post office both at the post office counter as well as at the doorstep through ubiquitous Postmen and Gramin Dak Sevak. Section 3 of the new Act empowers Central Government to decide on the services that can be rendered through post office in terms of the law in force at the time in respect of such service. The new Act has 16 sections as compared to 77 in the old Act. 1898 Act focused on postage stamp, postal article and money order whereas 2023 Act focuses on Service, Postage Stamp and Address.

Siddaramaiah to meet Rahul Gandhi: Will Karnataka have more Deputy CMs?

New Delhi: The big question on the tenure of Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will be discussed during a meeting with Congress leader Rahul Gandhi. According to News9's Gautam Shankar, who is tracking the development from Bengaluru, both Siddaramaiah and Gandhi are scheduled to meet in New Delhi on Thursday (April 3). DK Shivakumar, who currently holds the post of DY CM, is also in the national capital to hold talks with the Congress High Command. The 62-year-old Kanakapura MLA also holds portfolios of water resources and Bengaluru development departments apart from the president of the Karnataka Pradesh Congress Committee (KPCC).

In a significant development, Karnataka Forest Minister Eshwar Khandre also left for the national capital at 5am on Thursday. The visit of the minister wasn't initially part of the schedule. The move has sparked speculations of Khandre being the frontrunner to replace Shivakumar as the KPCC president. This comes as AICC leadership aims to balance the caste

equation with the KPCC president post as the Congress eyes Lingayat voters.

Siddaramaiah is set to propose the creation of two additional posts of Deputy Chief Ministers (DY CMs) in his 30-minute meeting with Gandhi. The Varuna-elected MLA will express his wish to continue as the CM after the completion of his two-and-a-half-year tenure at the end of 2025. The meeting has been arranged by All India Congress Committee (AICC) General Secretary KC Venugopal. The supporters of Shivakumar camp have been vouching for his elevation to the CM's post with many publicly stating that he will take the oath in December most likely and complete his remaining tenure of 2.5 years. It was widely speculated that the rotational CM could be the possible way given that both Siddaramaiah and Shivakumar vied for the CM post.

It will be interesting to see whether Shivakumar will be able to convince the Congress top leadership for his long-term ambitions or will Siddaramaiah manage to complete his full term given that he won't contest in Assembly elections anymore.

Trump's tariff gambit: Global shake-up, India's balancing act, and the Modi template

New Delhi: "It's the economy, stupid!" was the defining message in the 1992 US presidential campaign. Coined by Bill Clinton's campaign manager, James Carville, the postulation rings true today like never before.

US President Donald Trump has reset the global trade order bringing in a new alarming sense of unilateralism to tariffs. As the world paces to decode the impact of the Trump tariff card, it is clear that multilateralism has been buried down under. Under the weight of the tariff tsunami, world trade bodies are scurrying for cover.

The Trump order has not come totally unexpected but what is an element of total surprise is the acute element of bilateralism that would determine the trade reset among nations.

While trade pundits get to assess the full impact country wise, let us for a moment get to pivot away from economics to politics. Let us begin with Trump himself. He has played perfectly to his core constituency telling it that he is the ultimate boss man, an avatar he



has donned to 'Make America Great Again'. The messaging from his camp will get louder in the days to come when he is positioned as a leader who defies his friends and foes alike to put America first in his scheme of things. Any legitimate outcry on very likely fears of inflation soaring coinciding with recession engulfing America would be sought to be drowned in the cacophony of 'Make America Great Again'. Mark Trump's domestic and international ratings in the days to come as they hit the roof. A new template for power has just been announced.

The tiered tariff order would obviously have a tiered response globally with

the majority of the countries being at a receiving end. This means the majority of global leaders would take a beating in their respective ratings in their core constituencies.

From China to Vietnam and Japan to South Korea, the new tariff card would mean a set back to their economies, at least in the short to medium term, while their serving leaders would find it difficult to take the dressing down, especially in their domestic constituencies. What would the Trump tariff diktat mean to India under Prime Minister Narendra Modi? The economic impact, from initial estimates, would be in the range of \$30 to 35 billion dollars annually, which again would come down once we formally hear of pharmaceutical being excluded. It is interesting to note that while Trump slapped a 26 per cent tariff on India, he left out pharmaceuticals simply because generics from India shape up the health of the American citizen. Smart politics from Trump and a leeway to the Modi government.

वक्फ विधेयकावर मध्यरात्रीची चर्चा, अमित 'शाहांचा वॉशरूम ब्रेक' आणि लॉबीची बदललेली व्याख्या; विधेयक मंजुरीआधी नाट्यमय घडामोडी!

नई दिल्ली: वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्री मंजूर झालं. २८८ विरुद्ध २३२ अशा फरकाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मात्र, मध्यरात्री १२ नंतर विधेयकावर घेतलेल्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घेतलेला वॉशरूम ब्रेक चर्चेचा विषय ठरला. या मुद्द्यावरून विरोधी बाकांवरून काँग्रेस सदस्यांनी गोंधळ घातला खरा, पण अवघ्या काही मिनिटांत त्यांना त्यांच्याच दोन खासदारांमुळे माघार घ्यावी लागली!

लोकसभेत बुधवारी मध्यरात्रीनंतर जवळपास दोन तास चाललेल्या मतदान प्रक्रियेनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तब्बल १२ तासांहून जास्त काळ चर्चा केल्यानंतर मध्यरात्री १२ वाजून ६ मिनिटांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलं. पुढचे जवळपास दोन तास मतदानाची तीन टप्प्यांत प्रक्रिया चालली. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे मतदानादरम्यान उठून सभागृहाबाहेर गेल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला. खुद्द अध्यक्षानी त्यांची ही कृती



रास्त असल्याची भूमिका मांडली. लोकसभेच्या संसदीय कार्य समितीने वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चेसाठी ८ तासच ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात ही चर्चा १२ तास चालली. दोन्ही बाजूंनी आक्रमकपणे आपल्या भूमिका मांडण्यात आल्या. शेवटी मध्यरात्री १२ वाजता मतदानासाठी सादर केलेलं विधेयक २ वाजण्यासाठी २ मिनिटं शिल्लक असताना पूर्णांशाने मंजूर झालं! पण विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर मतदानावरून दावे-प्रतिदावे चालू असताना विरोधकांनी मात्र वेगळ्याच मुद्द्यावरून सरकारविरोधात आघाडी उघडली. वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत

मतदानासाठी मांडल्यानंतर काही वेळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे उठून सभागृहाबाहेर जाताना दिसले. तात्काळ विरोधी बाकांवरून काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. मतदानादरम्यान अशा प्रकारे सदस्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

अमित शाह व राजनाथ सिंह यांच्यासाठी सभागृहाचे नियम वाकवले जात आहेत का? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. राहुल गांधी वगळता सर्वच काँग्रेसच्या खासदारांनी वेणुगोपाल यांच्यासह या मुद्द्यावर निषेध नोंदवायला सुरुवात केली. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सत्ताधारी बाकांवरून यासंदर्भात बाजू मांडली जाऊ लागली. दोन्ही मंत्री स्वच्छतागृहासाठी गेल्याचं भाजपा खासदारांनी सांगितलं. पण त्यामुळे काँग्रेस खासदारांचं समाधान झालं नाही. पण तेवढ्यात काँग्रेस खासदार गौरव गौगोई बाहेरून सभागृहात दाखल झाले. हे पाहून आता सत्ताधारी बाकांवरचे खासदार आक्रमक झाले.

रॅपिडोला कर्नाटकमध्ये दणका; उच्च न्यायालयाची बाइक टॅक्सीला बंदी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकारने रज्यात बाइक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. रज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाइक टॅक्सी धावणार आहेत. तर कर्नाटकमध्ये बाइक टॅक्सीला बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक निर्णय दिला ज्यानुसार कर्नाटकातील बाइक टॅक्सी ऑप आणि सेवा बंद करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे रज्यातील रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती बी.एम. श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या आदेशानुसार, या सर्व बाइक टॅक्सी सेवांना सहा आठवड्यांत बंद करावे लागणार आहे. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मोटर वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत ठोस नियम तयार करत नाही, तोपर्यंत या सेवा बंद राहतील. कंपन्यांनी बाइक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, पण न्यायालयाने त्यापेटाळून लावल्या. न्यायालयाने सांगितले की, वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. तसेच सरकारला बाइक

टॅक्सीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना कर्नाटकचे परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी म्हणाले, या प्रकरणाचा आम्ही सविस्तर अभ्यास करू. न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा अवधी आमहाला दिला आहे. तसेच योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यास सांगितलं आहे. त्यानुसार आम्ही काम करू. कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे आणि बाइक सेवा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य परिवहन विभागाने या कालावधीत आमच्यावर कुठलीही प्रतिकूल कारवाई करू नये. रॅपिडोला आता लाखो बाइक चालवणाऱ्या चालकांची चिंता आहे. आदेशाची प्रत मिळवल्यानंतर आम्ही योग्य त्या सगळ्या कायदेशीर गोष्टींचं पालन करू. एप्रिल २०२४ मध्ये बाइक टॅक्सी सेवा सुरू झाली आहे असं वकील अरुण कुमार यांनी कोर्टाला सांगितलं, मात्र त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी आता निदेशांचं पालन केलं पाहिजे आणि बाइक चालवणं थांबवलं पाहिजे. असेही न्यायालयाने सांगितलं. सदरचा निर्णय बेंगळूरूमधील ऑटो-रिक्षा आणि कॅब चालकांच्या सततच्या आंदोलनांनंतर आला आहे.

ताजमहालची मालकी कोणाकडे? उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यांच्यात काय वाद आहे

नई दिल्ली: देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाची जोरदार चर्चा होत आहे. अशात काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असून, आज राज्यसभेत याच्या मंजुरीसाठी मतदान होणार आहे. दरम्यान यामुळे वक्फशी संबंधित अनेक वास्तू आणि मुद्दे समोर येत आहेत. यामध्ये भारतातील सर्वात प्रसिद्ध वास्तू असलेल्या ताजमहालचाही समावेश आहे. दरम्यान ताजमहालच्या मालकीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू आहे. १७ व्या शतकातील हा ताजमहाल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचा आहे की त्याचा ताबा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या ताब्यात आहे हा वादाचा केंद्रबिंदू आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयीन लढाया, राजकीय वाद आणि धार्मिक दावेही झाले आहेत. पण अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. ताजमहालच्या मालकीबाबतचा वाद सर्वात प्रथम १९९८ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी फिरोजाबाद येथील व्यापारी इरफान बेदार यांनी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डकडे ताजमहालला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात यावे असा अर्ज केला होता. त्यावेळी त्यांनी ऐतिहासिक ताजमहालची देखभाल करण्याची जबाबदारीही आपल्याकडे सोपवण्याची विनंती केली होती. इरफान बेदार यांच्या अजानंतर, वक्फ बोर्डाने वर्षानुवर्षे ताजमहालचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला नोटीस बजावली. यामुळे ताजमहालच्या मालकीबाबत निर्णय होण्याऐवजी कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला. पुढे २००४ मध्ये इरफान बेदार यांनी ताजमहालची देखभाल करण्याची जबाबदारी मिळवी यासाठी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका काय? सुनील तटकरे पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलले

नई दिल्ली: बुधवारी लोकसभेमध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक लोकसभेत सादर होताच विरोधकांनी मोठा गोंधळ केल्याचं पाहायला मिळालं. दिवसभर आणि रात्री उशिरापर्यंत या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर मध्यरात्री या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने 288 मत पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 232 मत पडली. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. त्यानंतर आता या विधेयकावर राजकीय वतुळतून प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे खासदार सुनील तटकरे यांची प्रतिक्रिया देखील समोर आली आहे. आम्ही वक्फ सुधारणा विधेयकाकाला पाठिंबा दिला आहे, मुस्लिम समाजामध्ये विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर विधेयकाची अंमलबजावणी होईल. मुस्लिम समाजाला न्याय देणारे हे विधेयक आहे, समाज्याच्या प्रगतीसाठी हे विधेयक



आहे. आम्ही पाठिंबा दिला, समर्थन केलं, बोलल्याने समर्थन आहे हे सिद्ध होतं, असं तटकरे यांनी म्हटलं आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, इतर पक्षांची भूमिका काय होती, त्याबाबत मी बोलणार नाही. कोडी कोणाची झाली त्यावरही बोलणार नाही.

हे विधेयक धार्मिक नाही, वक्फ बाबत वास्तविकता समोर येण्यासाठी हे विधेयक आहे, असं यावेळी सुनील तटकरे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान या विधेयकावर चर्चे सुरू असताना लोकसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. विधेयक लोकसभेत सादर होताच विरोधकांनी गोंधळ घातला, तर सत्ताधारी देखील या विधेयकाच्या समर्थनाथं मैदानात उतरल्याचं पाहायला मिळालं. काल दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाली. त्यानंतर मध्यरात्री हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने 288 मत पडली तर विधेयकाच्या विरोधात 232 मत पडली. अखेर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.

अंडे उबालना भी नहीं आता..सैफ और करीना में कौन है बेहतर कुक?



बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उनके पति और एक्टर सैफ अली खान बी-टाउन के काफी पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। करीना और सैफ के फैस कपल को बहुत प्यार करते हैं और उनकी लाइफ से जुड़ी हर अपडेट के लिए काफी एक्साइटड रहते हैं। हाल ही में करीना ने बताया कि उन्हें और सैफ को साथ में कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। करीना ने बताया कि उनमें और सैफ में, सैफ ज्यादा अच्छे कुक हैं।

करीना कपूर और सैफ अली खान बहुत ही खास बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों को साथ देखना उनके फैस को काफी पसंद है। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक बुक लॉन्च के दौरान अपनी और सैफ की ईटिंग हैबिट्स और पसंद-ना पसंद को लेकर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि सैफ ज्यादा अच्छे कुक हैं और उन्हें खाना बनाना काफी पसंद है।

करीना ने अपनी न्यूट्रिनिस्ट रुजुता दिवेकर की बुक द कॉमनसेंस डाइट के बुक लॉन्च में बात की। उन्होंने कहा कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर का बना खाना खाने से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता। करीना ने बताया कि सैफ और उन्होंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया है। करीना ने कहा- हमें ये काफी पसंद है, इसलिए हमने इसे अपनी जीवनशैली बना लिया है। सैफ एक बेहतर कुक है, ये बात तो पक्की है। मैं तो अंडा भी नहीं उबाल सकती। करीना ने कहा कि वो अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं हैं और उन्हें कई दिनों तक एक ही चीज, जैसे कि उनका पसंदीदा खाना खिचड़ी, खाने को दे दी जाए तो वो आराम से खा सकती हैं। ये उनका कम्पर्ट फूड है, और वो लगातार पांच दिन यही खाना खा सकती हैं। करीना ने बताया कि उन्हें खिचड़ी में थोड़ा सा घी बहुत पसंद है और वो आराम से इसे खा सकती हैं। करीना ने बताया कि उनका कुक कई बार थक जाता है क्योंकि उन्हें 10-15 दिनों तक एक ही खाना बनाना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि कपूर खानदान के लोगों को पाया सूप पीना बहुत पसंद है।

'केसरी 2' बनेगी बॉक्स ऑफिस का सिकंदर?



हाल ही रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कर नहीं पाई। जिसके बाद अब लोग आने वाली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। इसी महीने अक्षय कुमार की 'केसरी 2' और सनी देओल की 'जाट' भी रिलीज हो रही है। ऐसे में फैस को इन फिल्मों से काफी उम्मीद है। 'केसरी 2' से अक्षय कुमार धमाल मचाने के मूड में हैं। हाल ही में आया फिल्म का टीजर लोगों ने खूब पसंद किया है। टीजर आने के बाद इस फिल्म का क्रैज और भी बढ़ गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि केसरी 2 अपने ओपनिंग डे पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म केसरी 2 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जो जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन लीड रोल में दिख रहे हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि केसरी 2 अपने रिलीज के पहले दिन 7 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है सही आंकड़े तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही आएंगे। इसी साल जनवरी में अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' को अच्छा परफॉर्मिंग मिला है। जबर्दस्त ओपनिंग के साथ अपने पहले दिन इस फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए थे। ऐसे में केसरी चैप्टर 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं।

के बाद ही आएंगे। इसी साल जनवरी में अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' को अच्छा परफॉर्मिंग मिला है। जबर्दस्त ओपनिंग के साथ अपने पहले दिन इस फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए थे। ऐसे में केसरी चैप्टर 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं।



125 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने किया 362 करोड़ का कारोबार

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सुपरहिट एक्टर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के कई फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने भी कई फिल्मों की हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होती हैं। आज हम आपको अजय के एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। ये फिल्म एक्टर की 100वीं फिल्म है। फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन ने कई सुपरहिट फिल्मों दी हैं। अजय ने फिल्म फूल और कटि से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। यह एक एक्शन फिल्म थी। अजय 1991 से फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। अजय देवगन ने बैंक टू बैंक कई शानदार फिल्मों की हैं। ऑनस्क्रीन अजय और तब्बू की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। हम आपको अजय की 100वीं फिल्म के बारे में बता रहे हैं अजय देवगन की 100वीं फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर है। यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को पर्दे पर आई थी। अजय के इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यह फिल्म अजय के करियर की शानदार फिल्मों में एक है। इस फिल्म में मराठा योद्धा तान्हाजी मालुसरे की कहानी दिखाई गई है। यह इतिहास पर बनी फिल्म है। फिल्म में अजय ने तान्हाजी का किरदार निभाया था। जो बेहद शानदार और तारीफ के काबिल था। इनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त थी।

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म को बनाने में 125 करोड़ खर्च हुआ था, जबकि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड में 362 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। शानदार कलेक्शन के साथ ही 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उनको तीन अवार्ड्स से नवाजा भी गया। इस फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला था।

पवन सिंह और मोनालिसा का हॉट रेन रोमांस, गाने में जबरदस्त किसिंग सीन से मचा...



भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और ग्लैमरस अदाकारा मोनालिसा की जोड़ी ने फिर से धमाल मचा दिया है। इन दोनों का सुपरहिट गाना 'जाए दा ऐ जान' इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस गाने में बारिश में फिल्माए गए रोमांटिक सीन और दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री ने फैस को दीवाना बना दिया है। भोजपुरी फिल्म 'जिंदी आशिक' का यह गाना यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोर चुका है। इसे अब तक दस करोड़ 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। गाने की रोमांटिक धुन और शानदार फिल्मांकन इसे और भी खास बना रहे हैं। इस गाने को पवन सिंह और कल्पना पटवारी ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है। गाने के खूबसूरत बोल और संगीत विनय बिहारी ने दिया है, जो इसे एक खास भोजपुरी टच देता है।

गर्मी में रोजाना कितने कप कॉफी पीना है सही?

दुनियाभर में कई लोगों की सुबह की शुरुआत कॉफी के साथ होती है। ये कई तरह से सेहत के लिए फायदेमंद होती है। कॉफी में कैफीन होता है, जो थकान को कम करने, एनर्जी प्रदान करने और एक्टिव रहने में मदद करता है। इससे वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है। अगर इसे सही तरीके और सीमित मात्रा में पिया जाए तो ये कई तरह से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होती है।

कई लोग तो कॉफी पीने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दिन में तीन से चार बार इसे पीते ही हैं। कॉफी कई तरह की होती है एस्प्रेसो, कैपुचिनो, लैटे सबसे आम हैं, जिसे हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक पीना पसंद करता है। कई लोग इसमें दूध मिलाकर, तो वहीं कई लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, ऐसे में गर्मी के मौसम में एक दिन में कितनी कॉफी पीनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट से एक दिन में कितनी कॉफी पीएं?

दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शन डिजीज में कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित बंसल का कहना है कि गर्मी में कॉफी एक सीमित मात्रा में पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है और इस मौसम में कॉफी ज्यादा पानी से शरीर में डिहाइड्रेशन, एसिडिटी और नींद न आने जैसी समस्या हो सकती है।

डॉक्टर का कहना है कि गर्मी के मौसम में एक दिन में 1 से 2 कप कॉफी पीना काफी होती है, खासकर वो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। ब्लैक कॉफी कैफीन ज्यादा स्ट्रॉंग होती है, जिससे पसीना ज्यादा आ सकता है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जबकि दूध वाली कॉफी



ब्लैक या दूध वाली कॉफी, कौन-सी है सही?

कई लोग दूध वाली तो वहीं कुछ लोग ब्लैक कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन इन दोनों में से ब्लैक कॉफी को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ब्लैक कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। वहीं दूध से बनी कॉफी में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है। ब्लैक कॉफी वजन कम करने, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अपनी पसंद के साथ ही शरीर की जरूरत के मुताबिक ही इसका सेवन करना चाहिए।

थोड़ी हल्की होती है और पेट पर नरम असर डालती है। अगर आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है तो गर्मी के मौसम में इसे पीते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। यदि कॉफी पीने से चक्कर, घबराहट या पेट में जलन जैसी दिक्कतें होती हैं, तो तुरंत इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए कॉफी?

जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, नींद न आने या हार्ट से जुड़ी समस्या है, उन्होंने कॉफी पीने से परहेज करना चाहिए या एक सीमित मात्रा में ही इसे पीना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी कम मात्रा में ही कॉफी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद ज्यादा कैफीन बच्चे के विकास पर असर डाल सकता है।

केदारनाथ रूट पर फैला ये खतरनाक वायरस, अलर्ट मोड पर धामी सरकार

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ी और टेंशन भरी खबर आई है। यह खबर यात्रा में शामिल होने वाले घोड़े और खच्चरों की बीमारी से संबंधित है। यात्रा रूट पर चलने वाले 12 घोड़े और खच्चरों में खतरनाक वायरस एक्वाइन् इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है; मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बुधवार को ही राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस संबंध में सचिवालय में बैठक की।

उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी यात्रा में इस वायरस से ग्रसित घोड़े या खच्चर शामिल नहीं होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े और खच्चरों की ठीक से स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यात्रा रूट पर एक भी घोड़ा या खच्चर इस वायरस से ग्रसित पाया गया तो इसका खामियाजा संबंधित अधिकारियों को भुगतना होगा। इसलिए कोई भी अधिकारी इसे हल्के में ना ले और व्यक्ति रूप से पहल करते हुए सभी घोड़े एवं खच्चरों की जांच कराई जाए।

12 घोड़ों में मिला खतरनाक वायरस

बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी केवल रुद्रप्रयाग में ही 12 अश्ववंशीय पशुओं में यह वायरस मिला है, लेकिन सरकार ने यात्रा रूट पर चलने वाले सभी घोड़े एवं खच्चरों की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं, आसपास के इलाकों से आने वाले घोड़ों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल जिन पशुओं में यह वायरस मिला है, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह संक्रामक वायरस है और इसे रोकने के लिए रुद्र प्रयाग में दो क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें एक सेंटर फाटा में बनेगा। वहीं दूसरा कोटमा में बनाया जाएगा।

मुक्तेश्वर संस्थान होगी सैपल की जांच

उन्होंने बताया कि सरकार की पूरी कोशिश है कि चारधाम यात्रा में कोई भी रोगग्रस्त घोड़ा या खच्चर ना शामिल हो। उन्होंने बताया कि घोड़ों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जरूरी इन्फ्रारेड्क और दवाइयां उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक मुक्तेश्वर संस्थान में सभी घोड़े-खच्चरों के सीरोलॉजिकल सैपल की जांच होगी। राज्य के किसी भी जिले में इस वायरस से ग्रसित पशु मिलते हैं तो उन्हें तत्काल क्वारंटीन किया जाएगा।

कब खुलेंगे कपाट

उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुलनेकी तारीख घोषित हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसी प्रकार बदरीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। इसी प्रकार श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे।



मथुरा में बनेगा बांके बिहारी का स्पेशल बंगला, अब इसी में विराजमान होंगे महाराज

विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के फूल बंगले बनना प्रारंभ होने जा रहा है। जिसमें ठाकुर बांके बिहारी महाराज अब फूल बंगला में विराजमान होकर भक्तों को सुबह और शाम दर्शन देंगे। साथ ही ठाकुर बांके बिहारी महाराज के लिए फूल बंगला का कार्य देश और विदेशों से आने वाले फूलों से किया जाता है। सुबह और शाम मिलाकर लगभग 200 से अधिक फूल बंगले बनेंगे। ठाकुर बांके बिहारी महाराज फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे।

जानकारी के मुताबिक, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 8 अप्रैल से फूल बंगला बनाना प्रारंभ हो जाएगा। जिसमें ठाकुर बांके बिहारी महाराज 8 अप्रैल की सुबह से आने वाली हरियाली अमावस्या तक सुबह-शाम भक्तों को फूल बंगले में विराजमान होकर दर्शन देंगे और तो और गर्भ ग्रह से बाहर निकल कर जगमोहन में विराजमान होंगे।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठाकुर बांके बिहारी महाराज फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। वहीं इस बार 200 से अधिक फूल बंगले ठाकुर



बांके बिहारी महाराज के बनाए जाएंगे और इन सभी फूल बंगलों में ठाकुर बांके बिहारी महाराज विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। फूल बंगला बनाने में कितनी आती है लागत वहीं इस एक फूल बंगले की अनुमानित लागत लाखों रुपए में आती है और जब इन सभी फूल बंगलों की संख्या जोड़ दी जाए और उनकी कुल लागत निकली जाए तो करोड़ों रुपए होती है। सीधा-सीधा कहा जा सकता है कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज के बनने वाले फूल बंगलों में प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का खर्च होता है जो की भक्त अपनी आस्था अनुसार करते हैं।

भक्तों को फूल बंगले में दर्शन

वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बांके बिहारी मंदिर के सेवायक मोहन गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज के फूल बंगला 8 अप्रैल से बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठाकुर बांके बिहारी महाराज सुबह और शाम भक्तों को फूल बंगले में विराजमान होकर दर्शन देंगे। इस दर्शन को करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं। वहीं फूलों के बंगले बनाने का कारण होता है कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज को गर्मी से राहत प्रदान की जा सके।

